कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

विशाल रैली, डिब्रूगढ़ (असम) 6
भाजपा ने मणिपुर विधानसभा के उपचुनाव में दो सीटें जीतीं........ 8
गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव........ 9

सरकार की उपलब्धियां

नि:शक्तजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान........ 10
कैंसर और हृदय रोगियों को 90 प्रतिशत तक सस्ती दवाएं........ 10
दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत की विकास दर........ 11
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई पहल योजना........ 12

वैचारिकी

अब्दुल्ला द्वारा जुलाई समझौते का उल्लंघन, स्वतंत्र कश्मीर की रूपरेखा तैयार
पं. दीनदयाल उपाध्याय........ 13

हमारे प्रेरणास्रोत

अटलजी : एक अद्वितीय सांसद
–लालकृष्ण आडवाणी........ 15

लेख

अपने गिरेबां में झांके कांग्रेस
– बलबीर पुंज........ 17

अन्य

प्रधानमंत्री की मलेशिया और सिंगापुर यात्रा........ 19
जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन, पेरिस........ 22
संसद में बहस........ 25
डॉ. अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस........ 28
मन की बात........ 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को

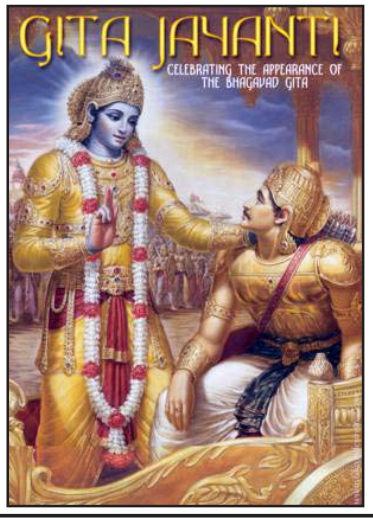

गीता जयंती

की हार्दिक शुभकामनाएं!

सोशल मीडिया से...

फेसबुक

श्री नरेंद्र मोदी

इस बारे में सोचें- क्या हम विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? यह शब्द अहम है, इससे हम 'attitude' में बदलाव ला सकते हैं।

.....

श्री अमित शाह

अनेकता में एकता की जो बेजोड़ मिसाल भारत ने सम्पूर्ण विश्व के सामने रखी है उसमें बाबा साहब द्वारा रचित संविधान का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 20वीं सदी में बने अधिकतर प्रजातान्त्रिक देश एक-एक करके अपने प्रजातंत्र को खोते चले गए, वहीं भारत में प्रजातंत्र लगातार मजबूत होता रहा। भारत में प्रजातंत्र का ऐसा उत्सव सिर्फ बाबासाहब अंबेडकर की ही दूरदर्शिता का परिणाम है।

.....

श्री जे.पी. नड्डा

आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पष्ट प्रमाणों के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफा नहीं देने तक भाजपा अपना आंदोलन जारी रखेगी।

.....

धर्मेंद्र प्रधान

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद एवं अन्य मंचों का बहुमूल्य समय शर्मनाक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, वह भी सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों का मानना है कि वे कानून से ऊपर हैं। वे यह समझने में विफल रहे हैं कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने वंश के आधार पर विशेष व्यवहार का दावा नहीं कर सकता।

twitter

श्री नरेंद्र मोदी *@narendramodi*

लोकतंत्र के सामने 2 खतरे हैं- मनतंत्र और मनीतंत्र। देश मनतंत्र से नहीं जनतंत्र से चलता है।

.....

श्री अमित शाह *@AmitShahOffice*

यदि विकास को जमीन पर उतारना है तो असम को भाजपा सरकार की जरूरत है। हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार का एक मंत्री पन्द्रह दिन में एक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे।

.....

श्री रविशंकर प्रसाद *@rsprasad*

2004 में जब भाजपा सरकार से हटी थी तो बीएसनल ने 10000 करोड़ रुपए से अधिक लाभ की सूचना दी थी। 2014 में जब भाजपा की वापसी हुई, बीएसएनल 8000 करोड़ रुपए के नुकसान में था।

पाथेय

संसार में एकता का दर्शन कर उसके विविध रूपों के बीच परस्परपूरकता को पहचान कर उनमें परस्परानुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही संस्कृति है। प्रकृति को ध्येय की सिद्धि के अनुकूल बनाना संस्कृति तथा उसके प्रतिकूल बनाना विकृति है। संस्कृति प्रकृति की अवहेलना नहीं करती, उसकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं करती बल्कि प्रकृति में जो भाव सृष्टि की धारणा तथा उसको अधिक सुखमय एवं हितकर बनानेवाले हैं, उनको बढ़ावा देकर दूसरी प्रवृत्तियों की बाधा को रोकना ही संस्कृति है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

संविधान दिवस : एक रचनात्मक पहल

देश के इतिहास में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। यह उस विरासत का उत्सव है जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संसदीय लोकतंत्र के रूप में हमें दिया। संसदीय लोकतंत्र की विरासत हमें भारत के संविधान से प्राप्त होता है जिसे इसके अभिनय एवं समावेशी स्वरूप के लिए पूरे विश्व ने सराहा है। पूरे विश्व में कहीं भी 'अनेकता में एकता' के सिद्धांत को इतनी खुबसूरती से मूर्तरूप नहीं दिया जा सका है। हमारे संविधान निर्माता अपने दूरदृष्टि एवं समावेशी चरित्र के कारण यह संभव कर पाये। भारतीय संविधान के मूल्य एवं आत्मा ने हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है तथा साथ ही हर व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। जिस दिन संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, उस दिन को याद कर राष्ट्र अपने नागरिकों को संविधान की मूल भावना एवं आदर्शों के प्रति और अधिक जागरूक कर रहा है।

संविधान दिवस पर संसद में हुए बहस से संविधान की मूल भावना का पुन:स्मरण हुआ है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर हुए इस बहस का विशेष महत्व है। इस बहस में गंभीरतापूर्वक भाग लने वाले सभी सांसदों का अभिनन्दन करना चाहिए। जहां एक ओर इस बहस की शुरुआत गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हुए की, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका समापन अपने प्रभावी उद्‌बोधन से किया। 'आइडिया ऑफ इंडिया' जिसका प्रतिपादन नरेन्द्र मोदी ने भारत के महान सभ्यतागत मूल्यों के माध्यम से जिस प्रकार से किया वह वास्तव में ऐतिहासिक है।

भाजपानीत राजग सरकार ने अनेक अभिनव पहल किये हैं जिनमें विशेष अवसरों को मनाने के निर्णय का हर वर्ग ने स्वागत किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को 'सुशासन दिवस' घोषित कर इस संदर्भ में जनचेतना विकसित करने का प्रयास हुआ है। अटलजी के नेतृत्व में सुशासन एवं विकास के लिये उठाये गये कदमों को कौन भुला सकता है। उनके जन्मदिवस को 'सुशासन दिवस' के रूप में मना कर देश की जनाकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इस निर्णय से यह प्रमाणित कर दिया है कि वह 'सुशासन' के लिए कृतसंकल्प है।

इस संदर्भ में 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित होना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। यह प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों तथा उनके सरकार के अथक परिश्रम का ही प्रतिफल है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। यह वास्तव में भारतीय सभ्यता एवं मेधा की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है। यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक विश्व का द्योतक है जो आधुनिक जीवन के तनावों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर मुक्ति पाना चाहता है और इन चुनौतियों से लड़ने में योग की प्रभावी भूमिका को स्वीकार भी कर रहा है।

देश में आशा एवं विश्वास का वातावरण बनाने के लिए भाजपा नीत राजग सरकार को बधाई देना चाहिए। इन विशेष अवसरों को मना कर न के भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के महान आदर्शों एवं संविधान की मूल भावना का स्मरण किया गया, बल्कि देश की जनता को उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी किया गया। संविधान दिवस, सुशासन दिवस एवं योग दिवस ऐसा सकारात्मक पहल है जिससे हमारे देश का लोकतंत्र एवं समाज और भी अधिक सुदृढ़ होगा। लोगों ने इन पहलों का स्वागत कर इनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है जिससे आत्मविश्वास से परिपूर्ण चेतनायुक्त भारत के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : विशाल रैली, डिब्रूगढ़ (असम)

परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है असम : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 नवंबर को असम के डिब्रूगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया और कार्यकर्ताओं से आगामी असम विधान सभा चुनाव में तन-मन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया।

श्री शाह ने नागा शांति समझौते और उल्फा नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश से भारत लाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर और असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी कहते थे कि भारत का विकास एकसमान नहीं हुआ है और देश का पूर्वी क्षेत्र देश के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष योजनाओं का सूत्रपात किया है और पूर्वोत्तर के विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वह रेल यातायात की बात हो, असम के गाँवों को राजमार्गों से जोड़ने की बात हो, राज्य में रेडियो और टेलीविजन चैनल लगाने की बात हो या फिर रोजगार सृजन करने के लिए मुद्रा बैंक, कौशल विकास अथवा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात हो। श्री शाह ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा असम के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए असम में राज्य के लोगों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर काम करने वाली सरकार की जरूरत है और ऐसी सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है।

श्री शाह ने कहा कि असम एक ऐसा राज्य है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम एक सुरक्षित सीमा की जरूरत समझते हैं। असम को किसी और चीज से भी अधिक एक विकास केंद्रित देशभक्त सरकार चाहिए और ऐसी सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि असम की गोगोई सरकार राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नहीं दे सकी है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ हाल में हुए समझौते को सही बताते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने से पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

भाजपा अध्यक्ष ने असम की कांग्रेस सरकार पर राज्य में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोक पाने में अक्षम होने का आरोप लगाया और कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को ताक पर रखकर कांग्रेस सरकार इस तरफ से लापरवाह है। उन्होंने कांग्रेस पर गुपचुप तरीके से एआईडीयूएफ से 'गुप्त समझौता' कर लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एआईडीयूएफ से गठबंधन कर के राज्य को बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से कैसे निजात दिला सकती है? श्री शाह ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से समझौता नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के रहते असम को अवैध घुसपैठों से मुक्त बनाना असंभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को चुनौती दी कि वे बजाए गुप्त समझौते के खुलकर एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल से बात करें।

भाजपा अध्यक्ष ने असम की तरुण

गोगोई की कांग्रेस सरकार को ललकारते हुए कहा कि असम सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और जितनी योजनाओं को केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए मंजूरी दी है और इसके लिए जितनी राशि आवंटित की है, उसका पाई-पाई का हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए ताकि राज्य की जनता को यह पता चल सके कि असम के विकास के लिए निर्धारित राशि का भ्रष्टाचार में किस तरह गबन किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि विकास की कई योजनाएं तो असम सरकार के कागजों में गुम होकर रह गई है। भाजपा अध्यक्ष ने असम में कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के इतने वर्षों तक शासन करने के बावजूद असम के गाँवों में 24 घंटे बिजली नहीं पहुँची है, गाँवों का सड़कों से जुड़ाव नहीं हुआ है, पीने योग्य पानी का अभाव है, स्वास्थ्य सेवायें बदतर हैं, स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है जबकि भाजपा शासित राज्य विकास के नित नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रदेश की जनता वर्तमान असम सरकार से पूछना चाहती है कि असम अभी तक विकास से महरूम क्यों है?

श्री शाह ने कहा कि भाजपा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने को प्रतिबद्ध है और केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के साथ ही इस दिशा में शुरुआत कर दी गई है। असम में बाढ़ की भीषण समस्या को रेखांकित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस समस्या के पूर्णकालिक निदान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा और भाजपा असम को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने राज्य के रेल नेटवर्क को डबल ट्रैक में बदलने का आश्वासन भी दिया।

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि असम परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा असम में विकास की एक नई शुरुआत करेगी जो हर तबके के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होगा।

उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि असम की वर्तमान कांग्रेस सरकार की नाकामियों को, उनके भ्रष्टाचार को और असम के लोगों को विकास से दूर रखने की उनकी नीतियों को असम के जन-जन तक पहुंचाएं और संकल्प लें कि असम में अगले विधान सभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाकर असम को विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर करेंगें। ■

शीघ्र ही इंटरनेट यूजर में भारत होगा अमेरिका से आगे

दिसंबर 2015 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 4020 लाख हो जाएगी। पिछले साल के मुकाबले इस संख्या में 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। आईएएमएआई और इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से लगभग 3060 लाख लोग अपने मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस करेंगे। इस साल अक्टूबर में ये संख्या 2760 लाख थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल जून तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 4620 लाख पार कर जाएगी। इसमें मोबाइस स्मार्टफोन से इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज्यादा होगी। वर्तमान में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है। दिसंबर के बाद अमेरिका को पीछे करते हुए इंडिया दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। 6000 लाख इंटरनेट यूजर्स के साथ चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंटनेट यूजर बेस है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 100 लाख से 1000 लाख तक पहुंचने में लगभग 10 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन ये आंकड़े महज 3 साल में 1000 लाख से 2000 लाख तक पहुंच गए। गौर करने वाली बात ये है कि ये संख्या मात्र 1 साल में 3000 से 4000 लाख यूजर्स तक पहुंच गई है। इन आंकड़ों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में इंटरनेट साक्षरता कितनी तेजी से बढ़ रही है।■

भाजपा ने मणिपुर विधानसभा उपचुनाव में दो सीटें जीतीं

मणिपुर में हालिया संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने दो सीटें जीतीं। यह चुनाव 21 नवम्बर को आयोजित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री थोंगम विश्वजीत सिंह तथा श्री खुमुकचम जॉय किशन ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया। 28 मई को दल-बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विधायकों-थोंगम विश्वजीत सिंह, खुमुकचम जॉय किशन को आयोग्य ठहरा दिया गया था। किन्तु मणिपुर हाई कोर्ट ने लुखोई सिंह के स्पीकर के आदेश को स्थगित कर दिया, जो वांगोई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। थंगमीबंद में जॉयकिशन ने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी

ज्योतिन वेखोम को 1907 वोटों से हराया था। इस क्षेत्र में वोटरों ने 85 प्रतिशत का रिकार्ड मतदान किया। पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक को 12104 वोट मिले जबकि वेखोम को 10197 वोट प्राप्त हुए। थोंगजु में 92 प्रतिशत वोटरों की रिकार्ड वोटिंग हुई, जिसमें बिश्वजीत ने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बिजॉय कोइजम (कांग्रेस) को 3213 वाटों से हराया। बिश्वजीत को 14106 वोट और कोइजम को 11393 वोट प्राप्त हुए। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष श्री ठा. चाओबा सिंह ने मीडिया को बताया कि ओकराम इबोबी सिंह सरकार के कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। लोगों ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को खारिज कर ठीक काम किया है।

श्री चाओबा ने कहा कि भाजपा अब मणिपुर में 2017 के विधानसभा चुनावों का रोडमैप तैयार करेगी ताकि सीमावर्ती म्यांमार से लगे राज्य का विकास हो सके, जो अब तक लम्बे समय से विद्रोह से ग्रसित है।

60 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस के पास 48 सदस्य, तृणमूल और नागा पीपुल्स फ्रंट के पास चार-चार सीटें हैं और लोक जनशक्ति पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास एक-एक विधायक हैं। अब भाजपा पिछले महीने गारोट्राइबल कौंसिल में बुरी तरह चुनाव हारने के बाद एक महीने में ही सत्ताधारी पार्टी की यह दूसरी पराजय है। ■

प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता

भारतीय जनता पार्टी की बिहार ईकाई ने 29 नवम्बर को वरिष्ठ पार्टी

नेता और गया टाऊन से सात बार चुने गए विधायक को नेता चुना है। श्री कुमार बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे।

गौरतलब है कि भाजपा विधायकों ने सर्वसम्मति से श्री कुमार को अपना नेता चुना, जिसके लिए पूर्व विपक्षी नेता श्री नंदकिशोर यादव उनका नाम इस पद के लिए प्रस्तावित किया। श्री यादव ने कहा कि मैं कई वर्षों तक पार्टी के अनेक पदों पर रहा हूं और अब अन्य लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। कुल 243 सीटों में से भाजपा ने विधानसभा चुनावों में 53 सीटें जीतीं हैं। श्री कुमार से गया टाऊन से सात बार विजय प्राप्त कर रिकॉर्ड स्थापित किया है।

श्री प्रेम कुमार अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) से हैं और वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे और वे उदार दिल के लिए प्रसिद्ध हैं। ■

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव

भाजपा के 200 से अधिक मुस्लिम प्रत्याशी विजयी रहे

गुजरात के हाल के चुनावों में मुस्लिम समुदाय के 200 से अधिक प्रत्याशी नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों और ताल्लुका पंचायतों में विजयी रहे। पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में लगभग 450 से अधिक प्रत्याशियों को खड़ा किया था।

अल्पसंख्यक समुदाय के भाजपा प्रत्याशियों ने अनेक सीटों पर कब्जा किया जो पहले कांग्रेस के पास थीं। भाजपा ने मुस्लिम पॉकेटों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी राजनीतिक सेंधमारी की है, जो पहले कभी कांग्रेस की सीटें मानी जाती थी। 2010 में भाजपा टिकटों पर 160 से अधिक मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर सामने आए हैं।

राजकोट जिले में गोंडल नगरपालिका से विजयी भाजपा उम्मीदवार श्री आफिस जकारिया ने कहा कि गोंडल में भाजपा उम्मीदवार के लिए लगभग 60-65 प्रतिशत मुस्लिमों ने वोट दिए क्योंकि उन्हें अपने कारोबार में बहुत लाभ हुआ।

कांग्रेस केवल मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती रही और उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। कांग्रेस ने केवल कागज पर ही मुस्लिमों से वायदे किए और कभी भी उन्हें हकीकत में नहीं लाया गया।

गिर-सोमनाथ जिले से भाजपा ने कुल 20 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए- इनमें से आठ उना नगर पालिका, आठ कोडोनार ताल्लुका पंचायत और चार गिर-सोमनाथ ताल्लुका में हैं। सोमनाथ टाउन की कुल आबादी का लगभग 50 प्रतिशत भाग मुस्लिमों का है और इस प्रकार भाजपा उम्मीदवारों की विजय से संकेत मिलता है पार्टी के लिए मुस्लिमों के बीच स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ■

गुजरात में भाजपा को छह नगर निगमों में भारी बहुमत प्राप्त हुआ

हाल में आयोजित गुजरात सिविक चुनावों में भाजपा के राज्य के सभी छह नगर निगमों में विजय प्राप्त की है।

छह नगर निगमों में वोटिंग 26 नवंबर को हुए जिनमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और वड़ोदरा शामिल हैं। जबकि 31 जिला पंचायतों, 230 ताल्लुका पंचायतों और 56 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। उल्लेखनीय है कि सभी नगर निगम पहले भाजपा के अधीन थे।

अहमदाबाद मेयर और भाजपा नेता श्रीमती मीनाक्षी बहन पटेल ने सीट जीतने के बाद कहा कि भाजपा ने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा।

उन्होंने मीडिया को बताया कि यह लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की विजय है। हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और यही बात लोगों का विषय रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सत्ताधारी भाजपा ने 56 नगरपालिकाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ■

मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव

भाजपा ने देवास विधानसभा सीट जीती

मध्य प्रदेश में हाल में हुए विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने देवास विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। वर्तमान भाजपा विधायक श्री तुकाजी राव पुआर की मृत्यु के बाद भाजपा ने देवास सीट पर कब्जा जमाए रखा, जहां पुआर की पत्नी श्रीमती गायत्री राजे पुआर ने कांग्रेस के जय प्रकाश शास्त्री को 30778 वोटों से पराजित किया। ■

सरकार की उपलब्धियां

नि:शक्तजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान

नि: शक्तजन देश के लिए मूल्यवान संसाधन हैं। उनके लिए ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिसमें उन्हें समान अवसर मिल सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तथा समाज में पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। भाजपानीत राजग सरकार नि:शक्तजनों सहित सभी के लिए पूरी सहभागिता, अधिकारों की रक्षा और समान अवसर को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में भी नि:शक्तजनों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। देश में शारीरिक नि:शक्तजनों के समग्र विकास के लिए सरकार ने पुनरूद्धार समेत कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 3 दिसंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत के साथ सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रव्यापी यह अभियान नि:शक्तजनों को सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने, विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने, स्वतंत्र जीविका तथा समावेशी समाज के सभी पक्षों में उनकी भागीदारी में सहायक होगा। अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यों के राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के पचास प्रतिशत को जुलाई 2018 तक नि:शक्तजनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा। देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा ए1, ए तथा बी श्रेणी के स्टेशनों को जुलाई 2016 तक नि:शक्तजनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा। मार्च 2018 तक देश में सरकारी क्षेत्र के परिवहन वाहनों को नि:शक्तजनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेजों का कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा नि:शक्तजनों के लिए पहुंच मानकों को पूरा करेंगे। श्री अरुण जेटली ने श्री थावरचंद गहलोत के साथ नि:शक्तजनों के लिए अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित समारोह में नि:शक्तजनों की अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री विजय सांपला उपस्थित थे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि प्रस्तावित स्मार्ट सिटी में नि:शक्तजनों की सुविधा के प्रावधान होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों को सुगम्य भारत अभियान सफल बनाने के प्रयास करने चाहिए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकलांग शब्द की जगह 'दिव्यांग' शब्द लाने पर विचार करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस अभियान को मिशन मोड में लेना समाज का दायित्व है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि नि:शक्तजनों की अधिकारिता के लिए सरकार की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें छात्रवृत्ति, मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए पृथक संस्थान तथा नई ब्रेल भाषा विकसित करना शामिल है। ■

कैंसर और हृदय रोगियों को 90 प्रतिशत तक सस्ती दवाएं

एम्स में पहला अमृत आउटलेट शुरू

कैं सर और हृदय रोगों के इलाज के खर्च को कम करने के लिए भाजपानीत राजग सरकार ने पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर 15 नवंबर को अमृत आउटलेट की शुरुआत की। इसके तहत रोगियों को रियायती दरों पर दवाएं बेची जाएंगी। अमृत (अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट) कार्यक्रम के तहत काफी किफायती दरों पर दवाइयां मिलेंगी। इसके तहत कैंसर और हृदय रोगों की 202 दवाइयों की कीमतें औसतन 60 से 90 फीसदी तक कम होने जा रही हैं। कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के खर्च को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 15 नवंबर को दिल्ली स्थित एम्स में देश का पहला अमृत आउटलेट शुरू किया जो बहुत ही रियायती दर पर दवाएं बेचेगा। भारत में ये रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि अमृत (इलाज के लिए किफायती दवाएं एवं भरोसेमंद प्रत्यारोपण) कार्यक्रम के तहत हम किफायती दर पर दवाइयां देना चाहते हैं। हमने कैंसर और हृदय रोगों की 202 दवाइयों की पहचान की है जहां कीमतें औसतन 60 से 90 फीसदी तक कम होने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह से 148 'कार्डियक इंप्लांट' केंद्र से दिया जाएगा और उनकी कीमत 50 से 60 फीसदी कम होगी। यह एक पायलट परियोजना है जिसे हमने एम्स में शुरू किया है। 15 दिनों

के बाद हम कार्यक्रम की समीक्षा करने जा रहे हैं और आने वाले समय में हम केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में इसे दोहराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि एम्स में जेनरिक दवा स्टोर है, जहां से मरीजों को मुफ्त में दवा दी जाती है। ऐसे जेनरिक दवा स्टोर सभी केंद्रीय अस्पतालों में खोले जाएंगे।

13,440 रुपये कैंसर की दवा 889 रुपये में

कैंसर की कुछ दवाएं 80 से 93 फीसद की कम कीमत पर मिलेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएलएल अमृत स्टोर संचालित करेगी। यह कंपनी बाजार दर पर काफी छूट के साथ दवाइयां और उपकरण बेचेगी। एम्स के निदेशक श्री एम सी मिश्रा ने बताया कि अमृत औषधालय केमोथेरेपी के लिए 'डोसेटाक्सेल 120 एमजी' 93 प्रतिशत छूट के साथ 888.75 रुपए में बेचेगा जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य 13,440 रुपया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल लाखों लोगों के कैंसर पीड़ित होने का पता चलता है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 28 लाख लोगों को कभी भी कैंसर हो सकता है और पांच लाख लोग हर साल इस रोग से मरते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में सालाना 1,45, 000 महिलाओं में स्तन कैंसर होने का पता चलता है। श्री मिश्रा ने बताया कि स्तन कैंसर की दवा का एक कोर्स 75,000 रुपए का होता है। रोगी को इसका 17 कोर्स लेने की जरूरत होती है। श्री नड्डा ने जेनेरिक मेडिसीन स्टोर का भी दौरा किया और कहा कि केंद्र सरकार उस हर सरकारी अस्पताल में इसे खोलने की योजना बना रही है जहां डॉक्टर बांड्रेड दवाइयां लिखते हैं। ■

दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत की विकास दर भारत ने चीन को पछाड़ा

विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ने से देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर चीन से आगे निकल गया है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत थी।

मैन्यूफैक्चरिंग में उछाल और खनन व सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में विकास दर बढ़कर 7.4 फीसद हो गई है। पहली तिमाही में यह मात्र सात फीसद थी। इस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था चीन की 6.9 फीसद विकास दर से आगे निकल गई है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अनुसार दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में व्यापार, होटल, परिहवन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं की वृद्धि सर्वाधिक 10.6 फीसद हुई। सुखद संकेत यह है कि दूसरी तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग की वृद्धि बढ़कर 9.3 फीसद हो गई जो कि पहली तिमाही में 7.2 फीसद तथा पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.9 फीसद थी। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली का कहना है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद निवेश के माहौल में सुधार होने लगा है। मैन्यूफैक्चरिंग के प्रदर्शन में सुधार आया है और आने वाले समय में निवेश में वृद्धि होने के आसार हैं।

व्यापार, होटल, परिवहन, दूरसंचार और सेवाओं से जुड़े प्रसारण क्षेत्र में इस दौरान 10.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। एक साल पहले इस क्षेत्र में 8.9 प्रतिशत वृद्धि रही थी। वित्तीय, रीयल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर 9. 7 प्रतिशत रही। बिजली, गैस, जलापूर्ति और दूसरी सेवाओं की उत्पादन वृद्धि आलोच्य तिमाही के दौरान 6.7 प्रतिशत रही। आंकडों के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि 27.57 लाख करोड़ रुपये रही जो कि पिछले साल इसी अवधि में 25.66 लाख करोड़ रुपये रही थी।

सीएसओ के आंकड़ों से पता चलता है कि खेती पर सूखे का असर पड़ा है। दूसरी तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्यन क्षेत्र की वृद्धि दर 2.2 फीसद रही। इस अवधि में पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन की वृद्धि दर 6 फीसद रही है। सीएसओ के अनुसार दूसरी तिमाही के दौरान खरीफ मौसम में अनाज के उत्पादन में -1.8 फीसद और दलहन के उत्पादन में -1.1 फीसद की नकारात्मक वृद्धि रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मात्र 2.6 फीसद है। जीडीपी के ताजा आंकड़ों से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर के मार्ग पर बरकरार रखने के लिए लंबित सुधारों की डोज तथा सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की दरकार है।

भारत ने चीन को पीछे छोड़ा

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.4 फीसद वृद्धि

के साथ भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस अवधि में चीन की वृद्धि दर 6.9 फीसद रही। दरअसल, इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट है, जबकि ब्राजील तथा रूस की अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन देखने को मिला है। वहीं इस तिमाही में रूस और ब्राजील दोनों की अर्थव्यवस्था में 4.1 फीसद की कमी दर्ज की गई है। ■

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई पहल योजना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को एलपीजी सब्सिडी अंतरण पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स का प्रमाणपत्र सौंपा। इसके जरिये भारत में एलपीजी सब्सिडी अंतरण को दुनिया के सबसे बड़े नकदी अंतरण कार्यक्रम के तौर पर मान्यता दी गई है।

विदित हो कि एलपीजी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को राजग सरकार नये सिरे से 'पहल' नामक योजना के तहत शुरू किया। देश के 54 जिलों में 15 नवंबर 2014 से और फिर पूरे देश में एक जनवरी 2015 से इसे लागू कर दिया गया। पहल योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स ने दुनिया की सबसे बड़ी नकदी अंतरण योजना के तौर पर माना है। योजना के तहत 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार देश के 12.57 करोड़ परिवारों को सीधे सब्सिडी अंतरण उनके खातों में किया जा रहा है।

3 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार 14.62 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना में शामिल हुए हैं और उन्हें गैस सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है।■

डॉ. अंबेडकर की याद में प्रधानमंत्री ने जारी किए दो सिक्के

डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिसंबर को बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में 125 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए।

इस अवसर पर दिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोग उनसे अकसर पूछते हैं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी के बारे में हम जानते थे लेकिन आप 26 नवंबर कहा से ले आए। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें यह सब सुनकर ताज्जुब होता है। उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि कभी भारत के इतिहास में ऐसा दिन आएगा जब सिक्कों पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर होगी।

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनमें बाबा साहेब के निधन के 60 वर्ष बाद भी जन चेतना में जीवित हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के सामने फिलहाल मौजूद मुद्दों के संदर्भ में जितना डॉ. अंबेडकर के विचारों को याद करेंगे, हम 'उनके दृष्टिकोण और समग्रता के उनके रूख का उतना ही अधिक सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान को पहचान मिली है लेकिन उनके आर्थिक विचारों तथा दृष्टिकोण को अब भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है और इसकी सराहना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के मंत्र को अहम बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी को अंबेडकर के विचारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश की एकता में डॉ. अंबेडकर के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता है। ■

वैचारिकी

अब्दुल्ला द्वारा जुलाई समझौते का उल्लंघन, स्वतंत्र कश्मीर की रूपरेखा तैयार

– दीनदयाल उपाध्याय

जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ प्रारंभ से ही कश्मीर के मुद्दे पर अपने राष्ट्रवादी अभिमत के लिए जानी जाती रही है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। आजादी के समय, कश्मीर में लड़ाई की स्थिति होने के कारण संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर भारत के साथ उसका संबंध जोड़ा गया, लेकिन यह भी प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह तबसे जारी है और आज राष्ट्रीय एकता की राह में रोड़ा बना हुआ है। उस समय शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र कश्मीर के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियों के चलते उनका यह मंसूबा पूरा नहीं हो सका। जनसंघ के तत्कालीन महामंत्री और विचारक राजनेता पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 11 मई 1953 को पांचजन्य में इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए लेख लिखा था। गतांक में हमने लेख का प्रथम भाग प्रकाशित किया था। प्रस्तुत है द्वितीय भाग:

भाग 6 न्याय विधान से संबद्ध है। इसके अनुसार कश्मीर राज्य का अंतिम और सर्वोच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी आदि सभी मामलों के लिए एक न्याय मंडल (Judicial Board) होगा। यह न्याय मंडल सदरे रियासत के द्वारा प्रधानमंत्री की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। न्याय मंडल के अतिरिक्त एक हाई कोर्ट भी होगा, जिसकी बैठकें जम्मू और श्रीनगर में होंगी। मूलभूत अधिकारों के संबंध में आदेश आदि देने का अधिकार दोनों न्यायालयों को होगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी नागरिक भारत सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन कर सकता है किंतु सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के और किसी भी विषय पर अपील नहीं की जा सकेगी।

भाग 7 प्रधानाकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में है। भारत के प्रधानाकेक्षक को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं रहेंगे।

भाग 8 भारत और कश्मीर के संबंधों की विवेचना करता है। यह संबंध तीन अनुसूचियों में वर्णित है जिसमें प्रथम अनुसूची वे विषय सम्मिलित हैं, जिनका संबंध रक्षा, विदेश नीति और यातायात से है। इन विषयों पर विधान बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होगा। इसके साथ ही एक और अनुसूची दी गई है जिसमें वे विषय सम्मिलित हैं जो सम्मिलिन पत्र के अनुसार तो भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र में हैं किंतु जिनमें परिवर्तनों की माँग की गई है। इसमें ध्यान देने योग्य यह है (क) भारतीय संसद में कश्मीर के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हुए नहीं होंगे वरन् वहाँ की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे। (ख) कोई भी संधि जो भारत का विदेशमंत्री दूसरे देशों के साथ करे और जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य का किसी भी प्रकार संबंध आए, वह कश्मीर की सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकेगी और भारतीय संसद को उस संधि को व्यावहारिक रूप देने के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार न होगा। (ग) भारतीय संसद के अध्यक्ष कश्मीर के किसी भी संसदीय सदस्य को उसकी मातृभाषा में भाषण करने की अनुमति नहीं दे सकेंगे। वह भाषण वहाँ की राजकीय भाषा अर्थात् उर्दू में ही हो सकता है। (घ) भारत के सुप्रीम कोर्ट को विभिन्न राज्यों एवं राज्य और संघ सरकार के बीच उत्पन्न सभी विवादों के लिए मूल न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं किंतु वह न तो कश्मीर के संविधान के संबंध में और न उन विषयों के संबंध में, जिनके लिए भारतीय संसद को कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेगा। (च) यदि किसी विषय पर भारत और कश्मीर दोनों ने नियम बनाए हैं और वे परस्पर विरोधी हैं तो जहाँ अन्य राज्यों में राज्य के नियम के ऊपर संघीय नियम को मान्यता होती है, वहाँ कश्मीर में राज्य के अपने नियम को ही मान्यता रहेगी। (छ) भारत को यद्यपि यातायात में सभी अधिकार प्राप्त हैं किंतु भारत का राष्ट्रपति किसी भी मार्ग को कश्मीर सरकार की सम्मति के बिना राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व का घोषित नहीं कर सकता। (ज) कश्मीर राज्य चाहे तो राज्य की पुरानी सेनाओं को रख तथा बड़ा सकता है। यदि उनका भारतीय सेनाओं के साथ किसी भी प्रकार से एकीकरण किया जाए तो

वह कश्मीर सरकार की सम्मति से ही हो सकेगा। कोई भी सेना का अंग, जो भारतीय सेना के साथ अभी तक संबद्ध नहीं हुआ है, भारतीय सेना का अंग नहीं समझा जाएगा और उनपर राज्य का ही अधिकार रहेगा। (झ) भारत यदि नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाता है तो वह कश्मीर की विधानसभा की सहमति के बिना उस राज्य पर लागू नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार वे सब लोग जो जम्मू और कश्मीर राज्य से सन् 1947 के झगड़ों के कारण पाकिस्तान (भारत नहीं) चले गए हैं, वे सब वापस आने पर नागरिक माने जाएँगे। (त) भारत यदि राज्य कर्मचारियों के लिए कोई संयुक्त जनसेवा आयोग बनाना चाहे तो उसे कश्मीर सरकार की पूर्व सम्मति प्राप्त करना आवश्यक होगा। (थ) भारत के राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य में आंतरिक दुर्व्यवस्था होने पर तब तक संकटकालीन स्थिति की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त नहीं जब तक वहाँ की सरकार प्रार्थना न करे। युद्ध जन्य संकटकालीन स्थिति की घोषणा करने पर भी संघ सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य को वही निर्देश दे सकती है, जो राज्य के प्रशासनिक मामलों में किसी प्रकार का दखल न दे। इसी प्रकार भारतीय संसद ऐसे समय में भी बिना कश्मीर की विधानसभा अथवा वहाँ की सरकार की सहमति के कोई कानून नहीं बना सकती।

कश्मीर सरकार ने अपने व्यापारी प्रतिनिधि देश-विदेशों में रखने और किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, जिनमें व्यापार आदि की बातें हों, भाग लेने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

भारत की सुरक्षा के लिए तैयारी करने संबंधी नियम बनाने का अधिकार यद्यपि संघीय अनुसूची की प्रथम सूची के अनुसार भारत को स्वत: प्राप्त है, किंतु कश्मीर में उसके लिए कश्मीरी विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। संघीय सूची में से विषय क्रमांक 7 (संसद द्वारा सुरक्षा अथवा युद्ध के लिए आवश्यक घोषित उद्योग), क्रमांक 8 (केंद्रीय सूचना तथा चर विभाग), क्रमांक 9 (सुरक्षा, वैदेशिक मामले और भारत की सुस्थिति से संबंधित निवारक निरोध अधिनियिम) को कश्मीर राज्य ने भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र से निकाल लिया है।

रेल पथ यद्यपि संघीय विषय है किंतु यदि कश्मीर सरकार राज्य में कोई रेल बनाए या किसी कंपनी से बनवाएँ तो वह केंद्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी।

मुद्रा, बैंकिंग, पोस्ट आफिस आदि में केंद्र को कोई अधिकार नहीं रहेगा। जनगणना के लिए कश्मीर राज्य भारत की जनगणना से संबंध नहीं रखेगा और न उसका किसी प्रकार सर्वेक्षण विभाग से कोई संबंध रहेगा। चुनाव आयोग का अधिकार-क्षेत्र केवल राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन तक ही रहेगा।

भारत का कश्मीर के साथ किसी भी प्रकार वित्तीय एकीकरण नहीं होगा। वहाँ भारत कोई कर नहीं लगा सकता।

भाग 9 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह से सदरे रियासत एक जनसेवा आयोग नियुक्त करेगा। चुनाव कमीशन सदरे रियासत द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त होगा। भाग 11 उर्दू को राजभाषा स्वीकार करता है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई भी जिला कौंसिल किसी भी अनुसूचित भाषा को स्वीकार कर सकती है। भाग 12 में विविध प्राविधान दिए हैं जिनमें संकटकालीन स्थिति की अवस्था में प्रधानमंत्री की सलाह से सदरे रियासत घोषणा कर सकता है कि किसी भी न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार करने का अधिकार नहीं रहेगा।

क्रमश:

जीवेम शरदः शतम्

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं डॉ. मुरली मनोहर जोशी, केन्द्रीय मंत्रीगण - श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री एम वेंकैया नायडू और श्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल एवं कमल संदेश के सम्पादक श्री प्रभात झा सहित अन्य सभी नेतागण एवं कार्यकर्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दीर्घायु की कामना करते हुए अभिलाषा रखते हैं कि वे चिरकाल तक पार्टी एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें।

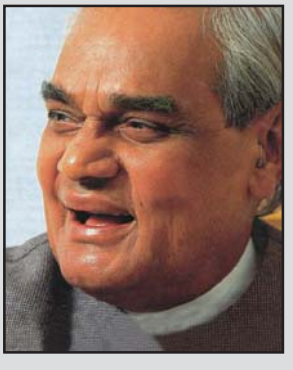

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
जन्म-दिवस : 25 दिसम्बर

अटलजी : एक अद्वितीय सांसद

लालकृष्ण आडवाणी

यदि मुझे किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना हो, जो प्रारम्भ से आज तक हमारे राजनैतिक जीवन का भाग रहे हों, जो लगभग 50 वर्ष से अधिक समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे हो, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूंगा कि वे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नेतृत्व को मैंने सदा स्वीकार किया है। बहुत से राजनीतिक प्रेक्षकों ने देखा होगा कि यह बात न केवल अनन्यतम रही है, बल्कि वास्तव में स्वतंत्र भारत के अभूतपूर्व भी रही है कि दो शख्सियतों ने आज तक एक ही संगठन में गंभीर साझेदारी के साथ मजबूत भावना से काम किया। मैं मानता हूं कि अटलजी के साथ इतनी लम्बी कामरेडशिप मेरे राजनैतिक जीवन का अमूल्य खजाना है जिस पर मुझे गर्व है।

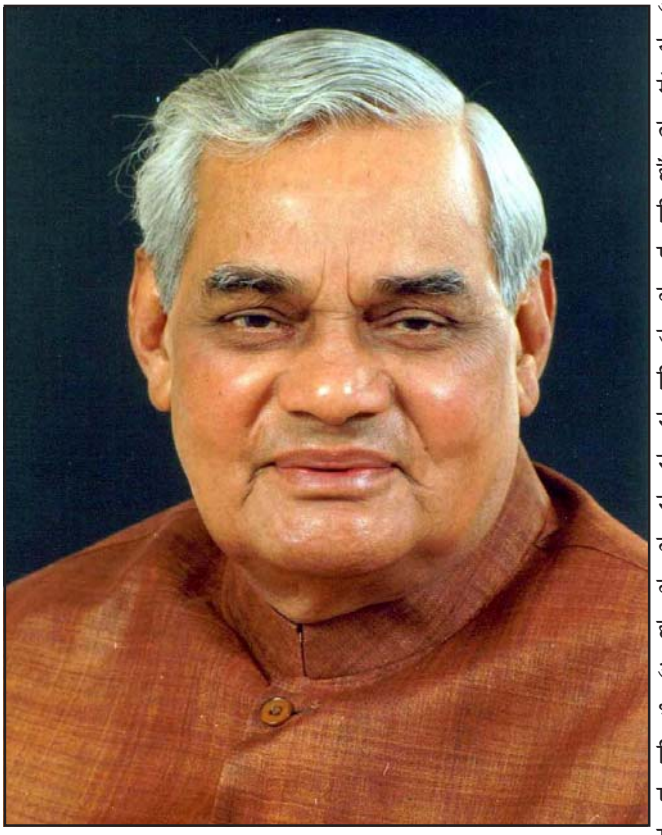

अनुभव ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में दीर्घकारी तथा सम्बन्धों को भरपूर करने वाला यह आपसी भरोसे, सम्मान और भारी लक्ष्यों के प्रति कुछ हद तक प्रतिबद्ध करता है। पावर प्ले से संचालित राजनीति स्वयं में ही प्रतिस्पर्धी और विवाद युक्त होती है। परन्तु समान विचार और समान आदर्शों तथा संस्कारों वाली राजनीति बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। जब उच्च प्रयोजन लोगों को एक मंच पर खड़ा कर देते हैं तो वे छोटे-छोटे मामलों और शख्सियत सम्बन्धी विषयों को एक तरफ कर देते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछा करते हैं कि अटलजी के साथ आपकी पार्टनरशिप 50 वर्षों तक कैसे चली? क्या आप में कभी भी इन्तर्भेद या समस्याएं नहीं आईं।

मैं इस प्रश्न की गुत्थी को अच्छी तरह समझता हूं। परन्तु मैं यह भी बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि जो कुछ भी लोग कहते हैं उसके विपरीत अब तक जो भी दशकों में अनुमान लगाए जाते रहे हैं अटलजी और मेरे बीच कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, लड़ाई की बात तो बहुत दूर की बात है। हां, हमारे विचारों में कभी-कभी भिन्नता हुई है। हम लोगों की शख्सियत अलग-अलग प्रकार की रही है और स्वभावत: कई अवसरों पर व्यक्तिगत घटनाएं और अनुभव अलग-अलग भी रहे हैं। यह बात किसी भी संगठन में स्वाभाविक है जो आंतरिक लोकतंत्र के मूल्यों को समझते हैं किन्तु हमारे सम्बन्धों में जिस बात ने गहराई तक पहुंचाया है, उसके पीछे तीन कारक रहे हैं। हम दोनों जनसंघ तथा भाजपा की विचारधारा, आदर्शों और संस्कारों से घिरे थे, जिसमें सभी ने राष्ट्र को सर्वप्रथम स्थान पर रखा और उसके बाद पार्टी और अंत में स्वयं के बारे में विचार किया। हमने कभी भी अन्तर-विवादों को आपासी भरोसे और सम्मान को निचली निगाह से नहीं देखा। परन्तु एक तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारक भी रहा है: मैंने सदैव ही निश्चय और अविवादास्पद रूप में अटलजी को अपना वरिष्ठ और अपना नेता स्वीकार किया है।

अपने सम्बन्धों के बहुत पहले से ही मैंने संगठन और राजनीतिक मामलों में जो कुछ भी अटलजी का निर्णय हुआ है, उसे स्वीकार किया है।

मैंने अपने विचार जरूर रखे परन्तु एक बार जब मुझे समझ में आ गया कि

अटलजी क्या चाहते हैं तो मैंने उनके विचारों और वरीयता को ही स्वीकार किया। मेरे रिस्पांस इतने प्रीडेक्टेबल होते थे कि पार्टी में मेरे कुछ सहयोगी या रा.स्व.सं. के नेता नाखुश हो जाते थे कि मैं क्यों अटलजी के निर्णयों के साथ असहमत नहीं होता हूं। किन्तु, इससे मेरे विचारों में कोई अन्तर नहीं आया कि अटलजी ने जो कुछ भी कहा, वह पार्टी के बारे में अंतिम शब्द होने चाहिए। बाद में, सरकार सम्बन्धी मामलों में भी यही स्थिति रही। मैं अपने सहयोगियों को कहा करता था कि 'कोई भी परिवार बिना मुखिया के नहीं रह सकता है, जिसके अधिकारों को नि:संदेह सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। दीनदयाल जी के बाद अटलजी हमारे परिवार के मुखिया थे।

यहां, मैं इतना और जोड़ना चाहूंगा कि अटलजी का मेरे प्रति पारस्परिक पहुंच का रूख रहा है। यदि वह समझते थे कि किस विषय पर क्या रूख होगा, और उस पर उनका कोई गहरा मतभेद न हो तो वह तुरंत कहते थे कि जो आडवाणी जी कहते हैं, वह ठीक है। इसके बाद चर्चा के लिए वह विषय तुरंत समाप्त हो जाता था।

एनडीए सरकार के छह वर्षों के दौरान मीडिया और राजनैतिक हल्कों में कुछ लोगों के लिए अटल-आडवाणी विवाद का विषय मौज-मस्ती उड़ाने का बना रहा था। अटलजी ने कई अवसरों पर इस अनुमान का संसद के अन्दर और बाहर खण्डन भी किया था। 'इंडिया टुडे' को दिए एक साक्षात्कार में, उनसे पूछा गया था: आपके गृहमंत्री श्री आडवाणी जी के साथ कैसे सम्बन्ध हैं? क्या भाजपा अनेक दिशाओं में नहीं फैल रही है? उनका तुरन्त जवाब होता था: मैं हर रोज आडवाणी जी से बात करता हूं। हम हर रोज सलाह मशविरा करते हैं। फिर भी आप अनुमान लगाते रहते हो। एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हममें कोई समस्या नहीं है। यदि कभी होगी तो मैं आपको बताऊंगा।

राजनैतिक जीवन के अपने लगभग छह दशकों में अटलजी ने न केवल अपने विचार-परिवार के विचारों और आदर्शों को प्रभावित किया है, परन्तु उनका वाक्-चातुर्य, बुद्धिमत्ता, राजनैतिक समझबूझ और रणनीति का सम्मान सभी राजनैतिक पार्टियों ने भी किया है। उनकी अद्भुत वक्तृत्व कला का प्रभाव न केवल संसद में बल्कि जीवन के हर प्लेटफार्म पर दिखाई देता था। उनकी जबर्दस्त आवाज संसद में निरन्तर गूंजा करती थी। अटलजी ने सोसाइटी के निचले तबकों की आवाज गुंजाने में कभी कोर-कसर नहीं छोड़ी।

राजनैतिक जीवन के अपने लगभग छह दशकों में अटलजी ने न केवल अपने विचार-परिवार के विचारों और आदर्शों को प्रभावित किया है, परन्तु उनका वाक्-चातुर्य, बुद्धिमत्ता, राजनैतिक समझबूझ और रणनीति का सम्मान सभी राजनैतिक पार्टियों ने भी किया है। उनकी अद्भुत वक्तृत्व कला का प्रभाव न केवल संसद में बल्कि जीवन के हर स्तर पर दिखाई देता था। उनकी जबर्दस्त आवाज संसद में निरन्तर गूंजा करती थी। अटलजी ने समाज के निचले तबकों की आवाज गुंजाने में कभी कोर-कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आम आदमी के कल्याण के लिए कई बिल (विधेयक) पेश किए। मुझे बड़ी खुशी है कि संसद में अटलजी द्वारा पेश विधेयकों के मूल रूपों और बहसों का सम्पादित अंश अप्पा घटाटे ने प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन के साथ अटलजी की विचारधारा और समसामयिक सांसदों को आने वाली पीढ़ियों तक उपलब्ध रहेंगी।

11 अक्टूबर 2011 को जन चेतना यात्रा की शुरूआत से पहले मैं उस शाम अटलजी से मिला और उनका आशीर्वाद मांगा। मेरी पिछली यात्राओं से पहले की तुलना में जो इस यात्रा में नहीं थी, वह थी कि अटलजी अपने खराब स्वास्थ्य के कारण भाग नहीं ले सके। परन्तु उनके समर्थन और आशीर्वाद से इस यात्रा का जो यह लक्ष्य था कि भ्रष्टाचार को मिटाया जाए और स्विस बैंक तथा अन्य देशों में जमा काले धन को भारत वापस लाया जाए, इसका भारी जवाब देखने को मिला है।

अटलजी, मैं और मेरी पूरी पार्टी दुर्दात भ्रष्टाचार और काले धन तथा सोसाइटी की अन्य बुराईयों के खिलाफ है। अटलजी द्वारा पेश यह बिल दिखाता है कि वह उनका निश्चय था कि वे अपने इच्छाशक्ति से आम आदमी के लिए इन्हें दूर करके ही रहेंगे।

मैं अटलजी को उनके स्वस्थ जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ■

(''अटल बिहारी वाजपेयी : ए कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंटेरियन'' पुस्तक की प्रस्तावना से)

लेख

अपने गिरेबां में झांके कांग्रेस

– बलबीर पुंज

संविधान दिवस पर संसद में बहस के दौरान एवं असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से उन लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए था जो संसदीय बहस पर जोर दे रहे थे और खासतौर पर पंथनिरपेक्षता के मुद्दे पर उनका बयान सुनना चाहते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ है। संविधान दिवस पर बहस के दौरान, श्री मोदी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि संविधान उनकी वैचारिकता और पवित्र ग्रंथ है। विपक्ष द्वारा उन पर असहिष्णुता के आरोपों की प्रतिक्रिया में, उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिक देशभक्त हैं और उन्हें बार-बार देशभक्ति का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ये और इसी तर्ज पर दिए गए अन्य बयानों को जोड़कर देखा जाए तो कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि श्री मोदी और उनकी सरकार किसी तबके को गैर-देशभक्त नहीं मानती। ये बयान उस विधिक स्थिति के भी अनुरूप हैं कि सामान्य कानून के अंतर्गत हर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक दोषी साबित न हो जाए।

संविधान में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसे किसी मत को प्रसारित करना शामिल नहीं है, केवल तब जब उसमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को हिंसात्मक रूप से अपदस्थ करना शामिल न हो। राजपुर के मार्क्सवादी चिकित्सक, अविरोक सेन, को हिरासत में रखे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में, छत्तीसगढ़ सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया था कि वो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ उपदेश दे रहे थे और ऐसे कृत्य राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को व्यवस्था पर भी सवाल उठाने का अधिकार है। उसी तर्क से, यदि कोई हिन्दू राष्ट्र या घर वापसी, राम मंदिर बनाने और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, तो सहिष्णुता एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति सम्बंधी नियम उसे अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार देते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के भीतर कुछ व्यक्तियों की एक निश्चित वैचारिकता हो, तो राज्य उनके निजी विचारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अनिवार्य रूप से इसका अर्थ यह नहीं होता कि राज्य उसके विचार के लिए प्रतिबद्ध है या उसका समर्थन करता है। फिर, क्यों मोदी विरोधी प्रत्येक बयान को पकड़कर मुद्दा बनाते हैं, जो कुछ भाजपा सदस्यों या राजग के मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं, और उन टिप्पणियों को पार्टी व उसके नेतृत्व में चल रही सरकार के रुख के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

हर दिन, विपक्षी दलों में से कोई एक दल अपने सदस्य के अनुचित बयानों से पल्ला झाड़ता नजर आता है। अगले ही दिन संप्रग सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे पी चिदंबरम ने कहा था कि सलमान रश्दी की पुस्तक सैटनिक वर्सेज को प्रतिबंधित करके कांग्रेस ने गलत कदम उठाया था। कुछ ही घंटों में कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई कि पुस्तक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था बल्कि उसका आयात करने पर रोक लगाई गई थी। प्रतिबंध लगाने या आयात पर रोक लगाने में फर्क क्या है। मायने यह रखता है कि श्री चिदंबरम तब नरसिम्हाराव सरकार में मंत्री भी थे जिसने पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने तब विरोध क्यों नहीं जताया था। यदि उस समय उनके मन में और भी विचार थे, तब वो और उनकी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि अन्य संगठनों के नेताओं के भी ऐसे ही विचार हो सकते हैं जब वे न धमकाने का निर्णय लेते हैं, न ही निष्कासित करने का, वाचाल सदस्य जब अपनी व्यक्तिगत धारणाएं जाहिर करते हैं जो पार्टी के आधिकारिक रुख से मेल नहीं खातीं।

इस अवसर पर, हमें सैटनिक वर्सेज

संविधान दिवस पर बहस के दौरान, श्री मोदी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि संविधान उनकी वैचारिकता और पवित्र ग्रंथ है। विपक्ष द्वारा उन पर असहिष्णुता के आरोपों की प्रतिक्रिया में, उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिक देशभक्त हैं और उन्हें बार-बार देशभक्ति का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ये और इसी तर्ज पर दिए गए अन्य बयानों को जोड़कर देखा जाए तो कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि श्री मोदी और उनकी सरकार किसी तबके को गैर-देशभक्त नहीं मानती।

पर प्रतिबंध की बात सामने लाने के लिए श्री चिदंबरम का आभारी होना चाहिए। इससे असहिष्णुता और उदारवाद पर कांग्रेस का खुद का रिकार्ड सामने आता है, उस समय जब वह उसी मुद्दे पर अपने प्रतिद्वंद्वी का विरोध करने में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त सैटानिक वर्सेज पर प्रतिबंध विरोधी विचारों के प्रति कांग्रेस की असहिष्णुता का एक मात्र उदाहरण नहीं है। पिछले सप्ताह, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहिष्णुता की सीख पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के द्वारा सरकार की खिंचाई कर रहे थे। वे पार्टी के इतिहास तक पहुंच गए, खासकर आजादी के बाद, उन्हें कई घटनाएं मिली होंगी जहां पार्टी नेतृत्व पार्टी के भीतर या बाहर विरोध को सहन नहीं किया। क्या श्री गांधी ने इस तथ्य की अनदेखी की कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह उन शीर्ष नेताओं को सुव्यवस्थित तरीके से दरकिनार किया जिन्होंने उस तरीके का विरोध किया जिस तरह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हिन्दू कोड बिल को लेकर आगे बढ़ रहे थे? नेहरू उन लोगों में से थे जिन्होंने संविधान को प्रारूपित किया मगर उदारवाद कहां चला गया था जब भारत के सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिक संहिता स्थापित करने की बात आई?

फिर नेहरू की पुत्री व उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी की एस निजलिंगप्पा, के कामराज और अतुल्य घोष जैसे कांग्रेसी नेताओं के प्रति असहिष्णुता देखने को मिली। ये नेता 1960 के उत्तरार्ध में कांग्रेस के अहम नेता थे और इंदिरा गांधी ने उन्हें दरकिनार कर दिया जिससे पार्टी में एक बड़ा विभाजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देश के संचालन में आम सहमति से चलने का प्रयास करेगी और बहुसंख्य विचारों को नहीं थोपेगी। क्या इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वही थी कांग्रेस की स्थिति? आपातकाल लागू होने के पूर्व ही, इंदिरा गांधी भारत का एक व्यक्ति, एक दृष्टिकोण, एक विचार वाले राष्ट्र के तौर पर पुनर्सरचनाकरण करने में लगी हुई थीं। ध्यान देने योग्य बात है, कि उन्होंने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान को समर्थन दिया जब उन्होंने अपने देश में एक दलीय सरकार थोपी थी। इसकी परिणति अंततः उनकी हत्या व बांग्लादेश में सैन्य तानाशाही के उभार के रूप में हुई। उदारवादी मुसलमान, विरोधी अर्थशास्त्री, जिन्होंने राज्य की आधिकारिक समाजवाद की नीति को चुनौती दी, इंदिरा गांधी के समय पूंजीवादी गठजोड़ का विरोध किया, उन्हें उनकी सरकार या अर्ध सरकारी संस्थाओं में कभी स्थान नहीं मिला। संप्रग सरकार ने एक दशक के अपने सत्ताकाल में इसी परम्परा को कायम रखा। श्रीमती सोनिया गांधी, जो सत्ता का असली स्रोत थीं, ने बहुत से मुद्दों पर विरोधी विचारों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं बरती। संप्रग सरकार के वर्षों में अल्पसंख्यकों का शरारतपूर्ण तुष्टीकरण हुआ, खासकर कट्टरपंथी रूढ़िवादी मुस्लिम धर्मगुरुओं व राजनेताओं का। जब इन कट्टरवादियों ने मुस्लिम समाज के अनुदार लैंगिक भेदभाव की आलोचना पर आधारित उनकी पुस्तक के लिए हैदराबाद में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन पर हमला किया, तब न तो आंध्रप्रदेश में कांग्रेस नीत सरकार न ही दिल्ली में सत्तासीन संप्रग सरकार ने लेखिका की रक्षा के लिए उंगली उठाई।

ऐसा लगता है, गांधी परिवार की सहिष्णुता कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने और वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण को असहिष्णुतापूर्ण बताने तक सीमित है। श्री गांधी, समान नागरिक संहिता का समर्थन करके या यह मांग करके कि औपनिवेशिक शासन के अधीन लिखी गई इतिहास की किताबों का पूर्वाग्रहरहित एवं पक्षपातरहित दृष्टिकोण परिलक्षित करने हेतु पुनरीक्षण व अद्यतन किया जाए। उदारवादी एजेंडे के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को स्थगित किए जाने पर खेद क्यों नहीं जताते हैं? श्री गांधी के लिए असहिष्णुता का शोर मचाना पुनः प्रासंगिकता हासिल करने का एक माध्यम मात्र है, जब उनकी पार्टी ने न केवल सत्ता खो दी है बल्कि नये भारतीय संदर्भ में अपना महत्व भी जिसमें आर्थिक उदारवाद और राजनीतिक स्व-जागरूकता भारत की हिन्दू विरासत के लक्षण हैं। ■

(साभार- पायनियर)

श्री गांधी, समान नागरिक संहिता का समर्थन करके या यह मांग करके कि औपनिवेशिक शासन के अधीन लिखी गई इतिहास की किताबों का पूर्वाग्रहरहित एवं पक्षपातरहित दृष्टिकोण परिलक्षित करने हेतु पुनरीक्षण व अद्यतन किया जाए। उदारवादी एजेंडे के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को स्थगित किए जाने पर खेद क्यों नहीं जताते हैं? श्री गांधी के लिए असहिष्णुता का शोर मचाना पुनः प्रासंगिकता हासिल करने का एक माध्यम मात्र है, जब उनकी पार्टी ने न केवल सत्ता खो दी है बल्कि नये भारतीय संदर्भ में अपना महत्व भी।

प्रधानमंत्री की मलेशिया और सिंगापुर यात्रा

व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने तथा निवेश आकर्षित करने हेतु हुए कई समझौते

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया और सिंगापुर की 21-24 नवंबर की चार दिवसीय यात्रा के दौरान व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने और भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए गए। मलेशिया में श्री मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री श्री नजीब रजाक, चीनी प्रधानमंत्री श्री ली केकियांग और जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे सहित कई अन्य विश्व नेताओं से वार्ता के अलावा आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। सिंगापुर यात्रा के दौरान श्री मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री श्री ली हिसयेन लूंग, राष्ट्रपति श्री टोनी टेन केंग याम और सेवामुक्त वरिष्ठ नेता श्री गोह चोक टोंग से मुलाकात की और दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। सिंगापुर की यात्रा संपन्न करने से पहले श्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया।

भारत-मलेशिया में साइबर सुरक्षा सहित तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के तीसरे दिन 23 नवंबर को भारत और मलेशिया ने साइबर सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर सुरक्षा समझौता इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम (सीईआरटी-इन) और मलेशिया की साइबर सिक्योरिटी के बीच हुआ। इस समझौते के तहत साइबर सुरक्षा घटना प्रबंधन, प्रौद्योगिकी सहयोग, साइबर हमलों और प्रचलित नीतियों से सरोकार रखने वाली सूचनाओं के आदान-प्रदान और इस क्षेत्र में दोनों देश एक-दूसरे की मदद करेंगे।

वहीं, दोनों देशों के सांस्कृतिक मंत्रालयों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह से बुनियादी ढांचा विकास समझौता भारत के नीति आयोग और मलेशिया के परफॉरमेंस मैनेजमेंट एंड डिलिवरी यूनिट (पेमांदु) के बीच हुआ। इन समझौतों पर श्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री नजीब रजाक की अगुवाई में दोनों

देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होने के बाद हस्ताक्षर हुए हैं।

मलेशिया के साथ मजबूत रक्षा सहयोग

श्री मोदी ने भारत के साथ मलेशिया के रक्षा सहयोग को मजबूत करने की बात कही। श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री नजीब रजाक के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं रक्षा सहयोग के लिए विशेष रूप से आपका आभारी हूं। इससे सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की हमारी साझा प्रतिबद्धता का पता चलता है। हम इस क्षेत्र में इस सहयोग को जारी रखेंगे।

भारत और मलेशिया ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी सहयोग पर भी सहमति जताई। आयुर्वेद और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में दोनों देशों के बीच और ज्यादा सहयोग की जरूरत को देखते हुए मलेशिया ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और दो थेरेपिस्टों की प्रतिनियुक्ति का स्वागत किया है।

आसियान देशों में शिखर पर रहा आतंकवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के नेताओं और चीन और जापान के अपने समकक्षों से बातचीत के दौरान आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय और समुद्री विवादों का जल्द समाधान किए जाने पर जोर दिया। पेरिस में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने इस बुराई से निपटने की जरूरत को रेखांकित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा और मेजबान मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री नजीब रज्जाक ने भी अपनी मुलाकात में इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी समूह की फैलाई जा रही नफरत की इस विचारधारा और बुराई के खिलाफ लड़ने का संकल्प किया।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में अपनी शुरुआती टिप्पणी में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक बड़ी वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है जो हम सभी को प्रभावित कर रहा है। हमारा आसियान के सदस्यों के साथ शानदार द्विपक्षीय सहयोग है। यह देखना चाहिए कि हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि को मंजूर करने की दिशा में सहयोग प्रदान करने समेत क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना सहयोग किस तरह बढ़ा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने चीनी समकक्ष श्री ली क्विंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंध और साझा वैश्विक हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि दोनों देशों को आतंकवाद के साझा खतरे से निपटने के लिए सामरिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। पेरिस और माली में हाल के आतंकी हमलों की निंदा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद की बुराई मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन से इतर हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात की जरूरत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इस बुराई से निपटने के लिए एकजुट हो।

श्री मोदी ने कहा कि देशों को अपने राजनीतिक मतभेद भुला कर प्रभावितों की मदद के लिए साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए सामरिक समन्वय बढ़ाने की जरूरत है। श्री ली ने कहा कि चीन आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच सहयोग से एशिया को और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

श्री मोदी ने अपने जापानी समकक्ष श्री शिंजो अबे से भी अलग से मुलाकात की और जापान को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे अहम विषयों पर चर्चा की। श्री अबे ने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में भारत-जापान संबंधों में सबसे अधिक संभावनाएं हैं।

श्री मोदी ने वैश्विक आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, साथ ही क्षेत्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। श्री मोदी ने भारत और आसियान के बीच भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए एक अरब डॉलर की कर्ज सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी साझा खुशहाली का रास्ता है। भारत-म्यामांर-थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे परियोजना की प्रगति की स्थिति अच्छी है और इसे 2018 तक बन जाना चाहिए।

आसियान कारोबार और निवेश शिखर सम्मेलन

18 महीने में बढ़ाया विदेशी निवेश: मोदी

21 नवंबर को आसियान कारोबार और निवेश शिखर

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 18 महीने में मुद्रास्फीति को कम करने के साथ उच्च जीडीपी वृद्धि दर की ओर उन्मुख होने और विदेश निवेश को बढ़ावा देने जैसे कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि सुधार अपने आप में कोई अंतिम बिंदु नहीं है। सुधार लंबी यात्रा के गंतव्य की ओर बढ़ने का एक मार्ग है। लक्ष्य भारत में बदलाव लाना है।

उन्होंने कहा कि मई 2014 में जब भाजपा नीत सरकार सत्ता में आई तब अर्थव्यवस्था उच्च राजकोषीय और चालू खाता घाटे से जूझ रही थी और आधारभूत संरचना परियोजना रुकी हुई थी तथा मुद्रास्फीति लगातार बनी हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट था कि सुधार जरूरी है। हमने अपने आप से सवाल किया कि किसके लिए सुधार? सुधार का लक्ष्य क्या हो? क्या यह केवल जीडीपी की दर में वृद्धि के आकलन के लिए हो? या समाज में बदलाव लाने के लिए हो। मेरा जवाब स्पष्ट है, हमें बदलाव लाने के लिए सुधार लाना है।

आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में निवेश करना फायदेमंद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को दुनिया भर के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है इसलिए निवेशकों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के देशों को स्वाभाविक साझीदार बताया और कहा कि इनके बीच संबंध प्राचीन काल से हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहता रहा हूं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। मैं ऐसा आसियान देशों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी अन्वेषकों के बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि देखी गई है। हम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सभी अन्वेषकों के बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा- साइबर सुरक्षा- नागरिक उड्डयन सहित 10 महत्वपूर्ण करार

भारत और सिंगापुर के बीच 24 नवंबर को रक्षा, साइबर सुरक्षा और नागरिक उड्डयन सहित सामरिक भागीदारी को लेकर 10 महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सिन लूंग की मौजूदगी में यह अहम करार हुए। दोनों देशों के बीच शहरी विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के सम्बन्ध में भी द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति भवन और सिंगापुर राष्ट्रपति के सरकारी आवास व कार्यालय इस्ताना की अंकित तस्वीर वाले साझा स्टैम्प्स को भी जारी किया। श्री मोदी का 24 नवंबर को इस्ताना स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति श्री टोनी तान केंग याम और सेवामुक्त वरिष्ठ नेता श्री गोह चोक टोंग से मुलाकात की।

न आंख झुका के बात करेंगे, न हम आंख दिखाएंगे: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 नवंबर को सिंगापुर में भारतीयों को संबोधित करते हुए कि ना आंख झुका के बात करेंगे और ना ही आंख दिखाएंगे हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि लिटिल इंडिया ने इस बार दिवाली की रोशनी को इस हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। इसके लिए सभी सिंगापुरवासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोई देश न सरकार से बनते हैं, न ही सरकार से बढ़ते हैं, देश बनते हैं जन-जन की इच्छाशक्ति की तपस्या से। उन्होंने कहा कि भारत सवा सौ करोड़ लोगों का देश है लेकिन फिर भी हमें सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना है। वसुधैव कुटुंबकम् यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और भारतीयों ने इस मंत्र को सच कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत जब सोने की चिड़िया था तब भी किसी को भी आंख खटकता नहीं था और हम हमारे बुरे दिन आए, तब भी किसी ने हमें अपमानित नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वक्त था, जब या तो डॉलर था या पाउंड। पहली बार हम रुपये के रूप में दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि अब पूरी दुनिया में भारत के प्रति विश्वास है। पहली बार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हम रुपया बांड ला रहे हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति उसमें निवेश कर सकता है।■

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन, पेरिस

प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद ने किया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में हो रहे विश्व सम्मेलन में भारत ने पृथ्वी के तापमान को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल कर एक अहम कदम उठाया है। इस पहल को पर्यावरणविदों ने महत्वपूर्ण बताया है। दरअसल, यह भारत द्वारा विकासशील देशों की आवाज बनने की कोशिश है और विकसित देशों की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करने का प्रयास है। साथ ही भारत ने न्यायोचित वैश्विक करार के लिए विकसित देशों पर प्रभाव भी बनाया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति श्री फ्रांस्वा ओलांद के साथ मिलकर 30 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया और विकसित तथा विकासशील देशों को साथ लाने वाली इस पहल के लिए भारत की ओर से तीन करोड़ डालर की सहायता का भी वादा किया। श्री मोदी ने इसके साथ ही ऐलान किया कि भारत हरियाणा के गुड़गांव में राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान के परिसरों में इस पहल की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इस पहल के तहत सचिवालयी ढांचागत निर्माण के लिए करीब तीन करोड़ डालर का योगदान देगा और अगले पांच साल के लिए इसके संचालन को मदद मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि हम पांच साल के लिए संचालन का समर्थन करेंगे और मिलकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दीर्घावधि कोष जुटाएंगे।

विश्व सौर गठबंधन की पहल कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत के नेतृत्व में यह समझौता विकसित और विकासशील देशों को नई राह दिखा सकता है। इसमें कम लागत पर स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का संदेश निहित है। इस करार से अन्य देशों को भी कम लागत में सौर ऊर्जा हासिल हो सकेगी। इस करार से ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्र (मकर और कर्क रेखा के बीच स्थित) में स्थित लगभग सौ देशों में सौर ऊर्जा कम लागत में हासिल हो सकती है।

श्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत के मौके पर कहा कि यह एक ऐसा गठबंधन है जो विकसित और विकासशील देशों, सरकारों और उद्योगों, प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को एक साझा उपक्रम में एकसाथ लाता है। इस पहल को 100 से अधिक देशों के समर्थन से शुरू किए जाने के मौके पर श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन नयी

उम्मीदों का सूर्योदय हुआ है... न केवल स्वच्छ ऊर्जा के लिए बल्कि उन गांवों और घरों के लिए भी जो अभी तक अंधेरे में हैं। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील विश्व अरबों लोगों को समृद्धि की ओर ले जा रहा है और ऐसे में इस ग्रह के लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद एक साहसिक वैश्विक पहल पर टिकी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि आधुनिक देशों को पर्याप्त 'कार्बन स्पेस' तो छोड़ना ही होगा ताकि विकासशील देश तरक्की कर सकें। उन्होंने कहा कि यही प्राकृतिक जलवायु न्याय' है। श्री ओलांद ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे बदलाव की मिसाल बताया। श्री मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो सपना मैंने लंबे समय से संजोया हुआ था, राष्ट्रपति ओलांद ने तुरंत आगे आकर उसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल का स्वागत करता हूं। संयुक्त राष्ट्र इसे सफल बनाने के लिए काम करेगा। सौर ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय परंपरा में, सूर्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत है।

उन्होंने कहा कि जैसा कि ऋग्वेद कहता है, 'सूर्य भगवान सभी प्राणियों, चर और अचर की आत्मा है। भारत में बहुत से लोग सूर्य नमस्कार के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, जब ऊर्जा के स्रोतों और औद्योगिक युग की ज्यादतियों ने हमारे ग्रह को संकट में डाल दिया है तो विश्व को हमारे भविष्य को रौशन करने के लिए सूर्य की शरण में जाना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से कहा कि भारत के पास 4 गीगावाट की क्षमता है और उसने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अगले साल की समाप्ति तक हम 12 गीगावाट जोड़ चुके होंगे। गौरतलब है कि सौर गठबंधन का विचार श्री मोदी ने ही पिछले महीने भारत-अफ्रीका फोरम शिखर वार्ता के दौरान पेश किया था।

श्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत फ्रांसीसी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए की और कहा कि 'मुश्किल घड़ी' में विश्व की शानदार तरीके से मेजबानी करने के लिए भारत दिल की गहराइयों से फ्रांस की सराहना करता है। उल्लेखनीय है कि प्रकृति के संबंध में उद्धरणों वाली एक किताब की प्रस्तावना श्री मोदी और श्री ओलांद ने संयुक्त रूप से लिखी है। इस किताब को भी इस मौके पर जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपनी किताब 'कन्वीनिएंट एक्शन'' का नया संस्करण फ्रांसीसी राष्ट्रपति को समर्पित किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनके साथ प्रस्तावना का सह लेखक बनकर मैं सम्मानित हुआ हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्राचीन समय से ही विभिन्न सभ्यताओं ने सूर्य को विशेष स्थान दिया है।' श्री मोदी ने आधुनिक देशों से विकास के लिए विकासशील देशों की खातिर पर्याप्त कार्बन स्पेस छोड़ने का आह्वान किया और कहा कि इससे विकास का एक ऐसा रास्ता बनेगा जिस पर कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे।

उन्होंने कहा कि इसलिए अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और ऊर्जा के बीच सम्मिलन से हमारा भविष्य परिभाषित होना चाहिए। बहुसंख्यक मानवता को बारहों मास सूर्य की भरपूर रौशनी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । फिर भी, बहुत से उर्जा स्रोत के बिना भी हैं। इसीलिए यह गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हम सौर ऊर्जा को अपनी जिंदगियों और अपने घरों में लाना चाहते हैं, इसे सस्ता बनाकर, अधिक भरोसेमंद बनाकर और ग्रिड से आसानी से जोड़कर। हम शोध और नवोन्मेष में सहयोग करेंगे। हम ज्ञान को साझा करेंगे तथा सर्वश्रेष्ठ कार्यों का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सौर क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे, संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहन देंगे और नवोन्मेषी वित्तीय प्रणालियां विकसित करेंगे। हम नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अन्य अंतरराष्ट्रीय पहलों के साथ भागीदारी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि मुझे उद्योग जगत की प्रतिक्रिया से खुशी है। इससे बेहिसाब आर्थिक अवसर पैदा होंगे जो इस सदी की नयी अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनेंगे।

जलवायु परिवर्तन पर सीओपी 21 शिखर सम्मेलन

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों को निभानी होगी जिम्मेदारी: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस की 29-30 नवंबर की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान अहम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में न केवल भाग लिया, बल्कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भी की। इस ऐतिहासिक सीओपी 21 शिखर सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन को कम करने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता साझा की। श्री मोदी ने इस यात्रा के दौरान जलवायु सम्मेलन से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा से मुलाकात की और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो एबे के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

श्री मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष श्री नवाज शरीफ ने भी जलवायु शिखर सम्मेलन से इतर अनौपचारिक मुलाकात' की। श्री मोदी ने इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री अशरफ गनी, मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री सखियागिन एल्बेगदोर्ज, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाला सिरीसेना और विश्व के कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की।

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु न्याय का नारा दिया

तथा विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करने के लक्ष्य हासिल करने के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने इसके लिए मिलजुल कर सस्ती तकनीक खोजने पर बल दिया। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापवृद्धि पर आयोजित सम्मेलन सीओपी-21 को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कार्बन उत्सर्जन एवं वैश्विक तापमान के लक्ष्यों पर बात करनी होगी लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी बात उन उपायों पर केन्द्रित हो जो इन लक्ष्यों को हासिल करने में दुनिया की मदद करें।

श्री मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत को 1.25 अरब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तेजी से तरक्की करनी होगी। भारत की इस आबादी में के 30 करोड़ लोगों की ऊर्जा तक पहुंच नहीं है। हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और इसके लोगों को अलग नहीं किया जा सकता। यह हमारी प्राचीन मान्यता है। हमारे यहां माना जाता है और मानव और प्रकृति एक है। इसलिए हमने 2030 तक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस समय तक हम प्रति इकाई जीडीपी के लिए उत्सर्जन सघनता को 2005 के स्तर से 33 से 35 फीसदी तक घटा देंगे। और हमारी स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा होगा।

श्री मोदी ने कहा हम इस लक्ष्य को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के जरिये हासिल करेंगे। उदाहरण के लिए 2022 तक हम 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। हम अपने वन क्षेत्र को इतना बढ़ा देंगे कि यह कम से कम 2.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले। हम लेवी लगा कर और सब्सिडी घटा कर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं। जहां भी संभव है हम ईंधन स्रोतों में बदलाव कर रहे हैं। शहरों और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बदल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी और सूरज डूबने के बाद अंधेरे में जी रहा है। उन्हें अपने घरों में उजाले और भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है क्योंकि वही लोग जैविक ईंधन से संचालित औद्योगिक युग के दुष्परिणामों के प्रति सबसे अधिक प्रभाव झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा की उपलब्धता और एक बेहतर जीवन के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण एक सार्वभौमिक आकांक्षा है। विश्व के अधिकांश देश बहुत कम कार्बन उत्सर्जन के साथ इस धरती की समृद्धि के लिए जुटे हैं और इसके लिए हमें बहुत से काम करने होंगे।

श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें जलवायु न्याय की भावना सुनिश्चित करनी होगी ताकि विकास के रास्ते में कुछ लोगों के जीवन की खातिर बहुत लोगों के अवसरों को खत्म नहीं किया जाए। विकसित देशों को विकासशील देशों को आगे बढने के लिए पर्याप्त जगह देनी होगी और हमें विकास के लिए कार्बन उत्सर्जन पर निर्भरता घटानी होगी।

उन्होंने कहा कि हमें सबको सुलभ स्वच्छ ऊर्जा को पाने के लिए एक साझेदारी बनानी होगी। नवान्वेषण जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने एवं जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए नवान्वेषण सम्मेलन बहुत अहम है। यही बात हमें एक साझा लक्ष्य के प्रति एकजुट करती है। ■

संसद में बहस

इंडिया फर्स्ट, संविधान धर्मग्रंथ : नरेंद्र मोदी

इस बार संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत 'संविधान के प्रति प्रतिबद्धता' विषय पर चर्चा से हुई। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधा को अंगीकार किए जाने की 65वीं वर्षगांठ और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के आयोजन के मौके पर संसद के दोनों सदनों में दो दिन के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में सर्वसमावेशी भाषण देते हुए कहा कि उनकी सरकार बहुमत से फैसलों की बजाय सहमति से आगे बढ़ने में यकीन रखती है। भाजपा सांसदों ने अपने तार्किक भाषणों से संविधान एवं लोकतंत्र के विभिन्न पहलूओं की विवेचना की। लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी शब्द का हुआ है, तो वो शब्द 'सेकुलरिज्म' है। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय वित्त तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, जबकि पड़ोसी देश में ऐसा नहीं हुआ।

गत 27 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा का समापन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान में कोई बदलाव आत्महत्या करने जैसा होगा। संविधान बदलाव को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। असहिष्णुता की बहस के बीच उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही धर्म है इंडिया फर्स्ट, एक ही धर्मग्रंथ है भारत का संविधान। सर्व पंथ समभाव को आइडिया ऑफ इंडिया बताते हुए उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार चला है और ऐसे ही चलेगा।

श्री मोदी ने कहा कि कोई भी संविधान नहीं बदल सकता है। इसे लेकर भ्रम जरूर फैलाया जा रहा है। बाबा साहब का दर्द संविधान में शब्द के रूप में उभरा। उन्होंने बहुत कुछ झेला, लेकिन संविधान बनाते समय देश के लिए सबसे अच्छी बातें शामिल कीं। उन्होंने अपमान का जहर पी लिया।

श्री मोदी ने अपने भाषण में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार डॉ. लोहिया ने नेहरू से कहा था कि तथ्य बता रहे हैं कि आपकी नीतियां काम नहीं कर रही हैं तो नेहरू ने जवाब में कहा था कि हां, मैं आपके बताए तथ्यों से इनकार नहीं कर सकता। पंडित नेहरू ने अपने इस बयान से अपने व्यक्तित्व और इस संसद की ऊंचाई को दर्शाया।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में 12 धर्मों के तरह-तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। यह इस देश की महानता है। दुनियाभर के धर्म यहां हैं और सद्भाव के साथ हैं।

श्री मोदी के भाषण के प्रमुख बिंदु:

- बाबा साहब का दर्द संविधान में शब्द के रूप में उभरा। उन्होंने बहुत कुछ झेला लेकिन संविधान बनाते समय देश के लिए सबसे अच्छी बातें शामिल कीं। उन्होंने जहर पी लिया।
- देश का एक ही धर्म संविधान है। आइडिया ऑफ इंडिया-पौधे में भी परात्मा होता है, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तुम नारायणी, नर करनी करे तो नारायण हो जाए।
- बोनस एक्ट की सीमा 3500 से बढ़ाकर 7 हजार किया जाएगा। एलिजिबिलिटी 10 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए की जाएगी।
- पहले कोई नियम नहीं था कि कोई कितने घंटे काम करेगा। बाबा साहब ने तय किया कि 8 घंटे काम होगा।
- एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि कोई संविधान नहीं बदल सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह आत्महत्या होगी। समाज का पिछड़ा तबका आरक्षण के सहारे आगे बढ़ेगा तो देश मजबूत होगा।
- श्री मोदी ने गांधी जी के एक बयान को याद करते हुए

उन्हें उद्धृत किया, 'पूंजीपति, जमींदार और किसान अपने हित की बात करते हैं। अगर सभी अपने अधिकारों की बातें करें और कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें तो अराजकता का माहौल बन जाएगा। अगर सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो कानून का राज कायम हो जाएगा। राजाओं को राज करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं है। किसानों और मजदूरों को अपने आकाओं का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है।'

- राजनेता ही खुद पर बंदिशें लगाते हैं। चुनाव में खर्च की सीमा जैसी तमाम चीजों के लिए नेता आगे आए।
- राजनेताओं को यह सोचना होगा कि लोग हमारे में बारे में राय बदलें।
- नरसिंह मेहता, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे लोगों ने समाज को बेहतर बनाने का काम किया। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई।
- हमारा समाज हजारों साल पुराना है। हमारे यहां भी बुराइयां आई हैं। लेकिन उसी समाज से निकले महापुरुषों ने बड़े काम किए। प्रधानमंत्री ने ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राममोहनरॉय को याद किया।
- प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। यह इस बात का उदाहरण है कि संविधान की ताकत क्या होती है और जब वह सही हाथों में होता है तो क्या होता है।
- लोकतंत्र में असली ताकत तब आती है जब सहमति बनती है। लेकिन जब सब विफल हो जाए तो अल्पमत और बहुमत की बात आती है।
- भारत में सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है। यही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनकी शक्तियां देता है। इस बात को बार-बार उजागर किया जाना चाहिए।
- सरकार का काम सिर्फ संस्थाएं बनाना ही नहीं, उनकी सीमाएं भी तय करना है।
- संविधान के 60 साल पूरे होने पर हाथी पर उसकी सवारी गुजरात में निकलवाई थी। मैं खुद उसके आगे-आगे चला था।
- सरल भाषा में कहूं तो हमारे संविधान का मूल भाव डिग्निटी फॉर इंडियन और यूनिटी फॉर इंडियन है। कई लोगों का नाम इतना बड़ा है कि कोई उनका नाम ले या नहीं, उनका नाम मिट नहीं सकता।
- संविधान में भी सभी की भूमिका रही है। इस संविधान की जितनी सराहना करें, कम है।
- लाल किले पर से बोल चुका हूं कि इस देश में सभी सरकारों ने काम किया है। किसी ने उम्मीद से थोड़ा कम किया होगा। इस देश को राजाओं ने नहीं बनाया है। इसे गरीबों, शिक्षकों, मजदूरों और किसानों ने बनाया है।
- यह बात सही है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर भी ऐतिहासिक दिन है। इस बात को भी उजागर करना अहम है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में निहित है।
- मैं भी अन्य सदस्यों की तरह एक सदस्य के तौर पर अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
- सदन में इस कार्यक्रम को लेकर जो रुचि दिखाई गई, इसके लिए मैं सभी सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

सेकुलर शब्द का दुरुपयोग बंद हो : राजनाथ सिंह

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में संविधान दिवस के अवसर पर चर्चा की शुरुआत करते केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम संविधान की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना अपमान झेलने के बाद भी बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी भारत छोड़ने की बात नहीं की। श्री सिंह ने कहा कि बाबा साहब हमेशा देश हित की सोचते थे, सामाजिक तिरस्कार के बावजूद उन्होंने परिस्थितियों को बदलने के लिए लगातार काम किया और संविधान का संतुलन इसका उदाहरण है।

श्री राजनाथ सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि बाबा

अंबेडकर ने दलित होने के चलते बहुत उपेक्षा झेली होगी, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी तीसरे देश में जाने की नहीं सोची। श्री सिंह ने कहा कि कुछ लोग अंबेडकर को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें केवल इस संकीर्ण विचारधारा से जोड़ना ठीक नहीं है।

सेकुलर शब्द को लेकर लगातार हो रहे विवाद पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेकुलर शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है लेकिन इसका मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता। इसका साफ मतलब है पंथनिरपेक्ष और इसी का इस्तेमाल होना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सोशलिस्ट और सेकुलर इन दो शब्दों को इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संशोधन के बाद डाला गया था।

बाबा साहब ने इन दोनों शब्दों का जिक्र संविधान के मूल प्रस्तावना में करना जरुरी नहीं समझा। उनका मानना था कि भारत के लोग मूल रूप से सेकुलर और सोशलिस्ट है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता हूं कि मैं उसे नहीं मानता हूं। जो हो गया सो हो गया। श्री सिंह ने कहा कि संविधान ने देश को एक दिशा दिखाई है। संविधान के निर्माण में तमाम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और एक संतुलित समाज दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर सच्चे अर्थो में एक राष्ट्र ऋषि थे।

उन्होंने संविधान के निर्माण में अपने अमूल्य योगदान से देश और समाज को एक दिशा दिखाई। 1997 में आजादी के पचास साल पूरे होने पर और 2012 में संसद की पहली बैठक के साठ साल पूरे होने पर विशेष बैठकों का आयोजन हो चुका है। इस बार डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है।

संविधान की वजह से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत : अरुण जेटली

गत 27 नवंबर को राज्यसभा में संविधान पर भाषण देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर को देश में केवल संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी उनका योगदान रहा। समाज में अन्याय के खिलाफ डॉ. अंबेडकर लड़े और देश को आगे बढ़ने का रास्ता भी उन्होंने बताया। बहुत कम वक्त में संविधान निर्माता समिति ने अपना काम पूरा किया। संविधान द्वारा देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई।

श्री जेटली ने कहा कि वर्ष 1947 में हुए बंटवारे के बाद हमारा देश मजबूत होता गया, लेकिन पड़ोस में (पाकिस्तान में) ऐसी स्थिति नहीं थी। संविधान की वजह से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ। संविधान के कारण हमारा चुनाव आयोग और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी संविधान बनाने में योगदान रहा। संविधान की मूल ताकत मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान निर्माताओं ने हमें दिए।

श्री जेटली ने आगे कहा कि संविधान में सुधार की भी जरूरत है। आपातकाल में लोगों का अधिकार छीना गया। सबसे बड़ा अधिकार जीने का है। संविधान में बदलाव कर जीने का अधिकार सुरक्षित हुआ। आज टीवी स्क्रीन पर कोई व्यक्ति गैरजिम्मेदाराना बयान भी दे दे तो उसे असहिष्णुता मान लिया जाता है।

उन्होंने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका में तालमेल जरूरी है। तालमेल गड़बड़ होने पर संविधान को नुकसान होता है। न्यायपालिका में आज जो हो रहा है वह संविधान के उलट है। अब अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता।

उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रकिया (कॉलेजियम सिस्टम) पर निशाना साधते हुए इसे डॉ. अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। न्यायपालिका की तरह ही संसद भी संविधान का अहम हिस्सा है।

उन्होंने यह भी कहा कि 70 के दशक में देश ने तानाशाही को देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 376 का काफी गलत इस्तेमाल हुआ है।

उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है, जिसका हमें सामना करना है। कई बार वोट की राजनीति के लिए किसकी कितनी निंदा की जाए, हम इसमें संकोच करते हैं।

जब देश पर संकट हो तो सभी को एक साथ आना होगा। सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम और कांग्रेस एक साथ हैं। ■

डॉ. अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस

सभी को डॉ. अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए : अमित शाह

भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर के 60वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को केन्द्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 'पुष्पांजलि' कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, संगठन महामंत्री श्री रामलाल, केन्द्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत एवं राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद श्री भूपेंद्र यादव, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार गौतम, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजेन्द्र गुप्ता, सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी तथा अनेक सांसदों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने डॉ. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।

पुष्पांजलि कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने डॉ. अम्बेडकर के जीवन को एक आदर्श बताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि वे डॉ. अम्बेडकर के जीवन से सीख लें। उनकी सकारात्मक ऊर्जा तथा देश के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा से हमारा देश आज भी एकजुट है।

उस समय के संविधान बनाने वाले महापुरूषों ने डॉ. अम्बेडकर को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाकर अच्छा ही किया था। डॉ. अम्बेडकर ने देश को एकजुट करने और समानता लाने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए। संघर्षों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी तथा गरीबों, दलितों, शोषित पीड़ित समाज के लिए सतत् मेहनत करते रहे। उनके जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और इस देश को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए देशवासियों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। श्री अमित शाह ने अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

केन्द्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि आज सुबह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर 125 रूपए तथा 10 रूपए के सिक्के जारी किए है। श्री गहलोत ने केन्द्र द्वारा गरीबों, दलितों, शोषित पीड़ितों के लिए जारी की अनेक योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से 26 नवम्बर को संविधान दिवस घोषित किया गया है। संविधान दिवस के माध्यम से देश की वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियां डॉ. अम्बेडकर की और संविधान के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। आगामी 26 जनवरी को राजपथ पर बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर पर एक झांकी को परेड में शामिल किया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री दुष्यंत कुमार गौतम ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का धन्यवाद किया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी योजना बना रही है, उससे समाज के सभी वर्गों का विशेषकर गरीबों और दलितों का कल्याण निश्चित होगा।

उन्होंने का कि जनधन योजना, कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना, मुद्रा योजना, भारत स्वच्छता मिशन आदि अनेक योजनाओं से देश के दलितों का भविष्य उज्वल हो रहा है। दलितों विशेषकर युवा वर्ग इससे लाभान्वित हो रहा है। देश के दलितों और गरीबों ने जो आशाएं भाजपा से बनाई हुई थी वे आशाएं अब पूरी होती जा रही हैं। देश का दलित पूर्णतया भाजपा के साथ हैं।

कार्यक्रम में भाजपा एवं अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, इनमें श्रीमती अनिता आर्या, श्री नारायण सिंह केसरी जी, श्री सत्यनारायण जटिया (सांसद), श्री रमेशचन्द्र रत्न (महामंत्री) श्री संजय निर्मल (राष्ट्रीय मंत्री), श्री किशनपाल केन, श्री वीरसिंह मथुरिया, श्री श्यामलाल मोरवाल, श्री वेंकटेश मोर्या सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। ■

जनजातियों के स्वाभिमान पर कोई चोट करे तो वे सहन नहीं करते : वसुंधरा राजे

मानगढ़ में आदिवासियों के बलिदान की स्मृति में 102 वर्ष पूर्ण होने पर आदिवासी बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वाधान में राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के आदिवासियों की आस्था के केन्द्र परम पूज्य गोबिन्द गुरू की कर्म भूमि मानगढ़ में 17 सितम्बर, 1913 को अंग्रेजों द्वारा धोखे से किये गए आदिवासिसों के नरसंहार की याद में एक भव्य जनसभा का आयोजन मानगढ़ के शिखर पर 17 नवम्बर, 2015 को किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने परम पूज्य गोबिन्द गुरू की धूणी को वन्दन कर व राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्मारक का अवलोकन कर उन्होंने श्हीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपस्थित अपार जनसमूह को सम्बोधित करते हुए श्री सुदर्शन भगत, पंचायती राज मंत्रालय, राज्यमंत्री, श्री मनसुखभाई वसावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यमंत्री ने अपने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए अनुसूचित जनजातीय से सम्बन्धित आदिवासियों के भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान की चर्चा की।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहां बलिदान हुए शहीदों की याद में हर वर्ष बलिदान दिवस मनाने व भव्य स्मारक व संग्रहालय बनवाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया ने कहा कि जनजातीय लोग सच्चे, वफादार, सहज व भोले-भाले होते हैं। किन्तु अगर इनके स्वाभिमान पर कोई चोट करे तो उसे वे सहन भी नहीं करते हैं। पंजाब में जालियावाला काण्ड में जहां सिर्फ केवल लगभग 400 लोग ही शहीद हुए थे वही मानगढ़ में लगभग 1500 से 2000 निर्दोष आदिवासियों को अंग्रेजों ने मार कर शहीद कर दिया था। ■

तमिलनाडु दौरे के बाद प्रधानमंत्री का एलान, चेन्नई को और 1000 करोड़

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 3 दिसंबर को हवाई सर्वेक्षण करने के बाद राज्य में राहत व पुनर्वास कार्यो के लिए और 1000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की घोषणा की। श्री मोदी ने नौसैनिक ठिकाने 'आइएनएस अडयार' से जारी एक बयान में कहा, 'राहत कार्यो के लिए भारत सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए तत्काल जारी किए जाएंगे। यह 940 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगा जिसे (केंद्र की ओर से) पहले जारी किया गया था'।

श्री मोदी के साथ राज्यपाल श्री के रोसैया और मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता भी थीं। श्री मोदी ने अपने संक्षिप्त बयान की शुरुआत तमिल भाषा में इस वाक्य से की जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से कहा, 'मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा'। श्री मोदी ने इसके बाद अंग्रेजी में कहा कि उन्होंने मानसून के प्रकोप से हुई क्षति और मुसीबत को देखा है। श्री मोदी के हवाई सर्वेक्षण में उनके साथ केंद्रीय मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन भी थे। श्री मोदी ने कहा, 'जरूरत की इस घड़ी में भारत के लोग तमिलनाडु के लोगों के साथ हैं'।■

जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए कहा कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि अब पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। तमिलनाडु में आई बाढ़ की वजह भी मोदी ने जलवायु परिवर्तन को बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताते हुए संकट की इस घड़ी में बचाव कार्यों में लगे दलों और लोगों की भी सराहना की।

फसलों के अवशेष जलाने के सवाल पर श्री मोदी ने कहा कि फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान का अंदाजा किसानों को नहीं था। उपाय क्या होते, इसका भी कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ और न ही इसके कारण होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अब इससे होने वाले नुकसान शहरों तक पहुंचने लगा तो यह सामने भी आया। श्री मोदी ने कहा कि फसलों के अवशेषों के ठूंठ के यदि छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो वो पशुओं के लिए चारा बन जाता है। फसलों के अवशेष जलाना पृथ्वी की चमड़ी जलाने के समान है। जैसे हमारी चमड़ी जल जाने पर जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा फसलों के अवशेष जलाने से होती है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा पूरे हिन्दुस्तान में ये हम लोगों की आदत है और परंपरागत रूप से हम इसी प्रकार से अपने फसल के अवशेषों को जलाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक तो पहले नुकसान का अंदाज नहीं था। सब करते हैं इसलिए हम करते हैं वो ही आदत थी। दूसरा, उपाय क्या होते हैं उसका भी प्रशिक्षण नहीं हुआ। और उसके कारण ये चलता ही गया, बढ़ता ही गया और आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, उसमें वो जुड़ता गया। और जब इस संकट का प्रभाव शहरों की ओर आने लगा तो जरा आवाज भी सुनाई देने लगी।

श्री मोदी ने कहा कि फसल के अवशेष भी बहुत कीमती होते हैं। वे अपने आप में वो एक जैविक खाद होती है। हम उसको बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं है अगर उसको छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाएँ तो वो पशुओं के लिए तो चारा बन जाता है। दूसरा ये जलाने के कारण जमीन की जो ऊपरी परत होती है वो जल जाती है।

श्री मोदी ने नि:शक्तजन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को नि:शक्तजन दिवस आने वाला है। यदि हम हमारी दृष्टि बदलें, इन लोगों को देखने का नजरिया बदलें तो ये लोग हमें प्रेरणा दे सकते हैं। हम छोटी सी मुसीबत पर रोने लगते हैं, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति, संकट को सामर्थ्य में बदलने की ललक से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है।

मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कश्मीर में आतंकवादियों की प्रताड़ना का शिकार हुए जावेद अहमद का जिक्र करते हुए कहा कि जावेद को 1996 में आतंकियों ने गोली मार दी थी। इस हमले में उन्होंने अपनी किडनी गंवा दी, स्पाइन इंजरी हो गई, पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य चला गया, एक आंख चली गई। लेकिन जावेद ने हार नहीं मानी। आतंकवाद की चोट भी उन्हें चित नहीं कर पाई। इतना सब गंवाने के बाद भी न कोई आक्रोश, न रोष। इस संकट को भी उन्होंने संवेदना में बदल दिया। जीवन को समाजसेवा में लगा दिया। अब जावेद बच्चों को पढ़ाते हैं। सार्वजनिक स्कूलों में कैसे ढांचागत सुधार हो इसी दिशा में काम कर रहे हैं, वह एक मौन क्रांति कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर कोने में जावेद जैसे प्रेरणाद्वीप जल रहे हैं।■